कैंसर की तरह तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार

शिवकुमार
शोध छात्र, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांश

इतिहास के बड़े घोटालों में से एक प्रतिभूति घोटाला जिसमें बैंकों के बड़े अफसर, सरकार के मंत्री और षेयर दलाल सरकारी नियम कायदों को लेकर जिस चालाकी से करोड़ों रुपये इधर–उधर करते रहे, उसे महाभ्रश्टाचार से कम क्या कहा जाये?[1] इसी तरह के कुछ बड़े–बड़े घोटाले आज देष की प्रतिश्ठा और सरकार की कार्यषैली पर वाट लगा चुके हैं। आज सरकार की ही लोक–लाज षर्मिंदा नहीं हुई बल्कि लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक का सर षर्म से झुक गया है।[2] आदर्ष–सोसाइटी घोटाला 2. G. Specterm और राश्ट्रमण्डल खेल घोटाला फिरॅण ठवदक के परत दर परत होते खुलासे और इन पर केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और ऊपर से सरकार का ध्यानाकर्शण कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को अलर्ट करना और जवाबी कार्यवाही में प्रधानमंत्री महोदय की सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सीमाओं में रहने की टिप्पणी ने सरकार के भ्रश्टाचार को खुले समर्थन को जगजाहिर कर दिया है।[3] भ्रश्टाचार के प्रति उदारीकरण की नीति ने आम जन को कंगाल बनाकर रख दिया है। संसदीय जनंतत्र में राजनीतिक तंत्र की खास भूमिका होती है।[4] मैंने अपने षोध कार्य में भ्रश्टाचार को प्राथमिक स्तर पर विकास कार्यों में अर्थात् ग्रामीण विकास कार्यों के संदर्भ में वर्णित कर उसका गहन विष्लेशण करने का प्रयास किया गया है।
[5]*(Footnotes)*[1]
Ministers Micsconducts" Written By 'A.G. Noorahie'[2] *lh-,e- >k % ''भ्रश्टाचार समस्या और समाधान'' ग्राम विकास के संदर्भ में पश्ठ–111–112* [3] *कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2015 व्हम 13 ''विकास योजनाओ में पारदर्षिता''* [4] *Article "History of corruption" James Moore. Times of India 2010*[5] *Article (Trasperensieinternational) Director Anupam jha 2009*

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

शिवकुमार , ''कैंसर की तरह तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार'', RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 127-133
http://anubooks.com/?page_id=2004
Artcile No. 18(RP567)

प्रस्तावना

यह एक जाना माना तथ्य है कि भारत का सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचार की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि आजादी के बाद भारतीय जन–जीवन में भ्रष्टाचार विश की तरह द्रुत गति से घुलता गया। आज वह चर्म पर है और आम जन–जीवन शैली का आवश्यक अंग बन गया है इसीलिए अब कालेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी हर्षद मेहता को अपने जीवन आदर्श के रूप में देखती है। आजादी के बाद से लगातार ऐसे उदाहरण समाने आते गए, जब सत्ता प्रतिष्ठान के शिखरों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गए। फिर भी सत्ता में उनका महत्त्व कम नहीं हुआ बल्कि वे और भी शक्तिशाली बनकर उभरें। राजनीति और भ्रष्टाचार का संबंध अन्योन्याश्रित हो गया। जिन लोगों को श्रेष्ठ मानकर हमने सत्ता की ऊँची सीढ़ी पर बैठाया, जिन्हें देखकर उल्लासित हो जाते, वे ही काले कारनामें में संलिप्त मिले। देश का भविष्य लिखने वाले तक इससे अछूते नहीं रहे और भ्रष्टाचार रक्त कैंसर की भाँति फैल गया।

ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार आजादी से पूर्व नहीं था। भ्रष्टाचार तब भी था तो सही लेकिन तादाद में ना के समान और स्वरूप में इससे भिन्न था। तब भ्रष्टाचार राजसत्ता की तरफ से नहीं था। वरन् इसकी जड़े नौकरशाही में ही और कुछ मात्रा में सूदखोर महाजनों में थी। ऐसा नहीं है कि उस समय शासक भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, वे कुछ भी कर सकते थे, शोषण, लूट, दमन इत्यादि कुछ भी लेकिन ऐसा कोई भी उदाहरण नजर नहीं आता। आजादी के बाद भ्रष्टाचार का एकदम नया संस्करण प्रकट हुआ जिसमें राजनेता प्रमुखता से संलिप्त थे और फिर नौकरशाह और पूँजीपतियों की संलिप्तता बढ़ती चली गयी। जब इन तीनों ही की तरफ से भ्रष्टाचार के मानदण्ड कायम होने लगे, तो वह रिस–रिसकर समाज की जड़ों तक पहुँचने लगा।

आजादी के शुरुआती वर्षो में भ्रष्टाचार के जो रूप सामने आये, उनमें टैक्स चोरी, सीमेंट से लेकर खाने–पीने तक की चीजों में भारी मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी और रिश्वत प्रमुख थे और इन सभी में राजनीतिज्ञों की सह थी। इस नवनिर्माण के दौर में रिष्वत, कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार की प्रचुर सम्भावनाएँ थी और बड़ी जगहों पर बैठे लोगों ने इन संभावनाओं का जमकर दोहन किया। पटवारी पतरौल अमीन से लेकर सरकारी नीतियाँ बनाने वाले आला अफसर तक हर कोई लूट रहा था। कोई ग्रामीण जनता को लूट रहा था तो कोई उद्योगपतियों से मिलकर बड़े काण्डों की व्यूह रचना में लगा था। तत्कालीन मशहूर पत्रकार **Frank Mores** के शब्दों में ''आजादी से पहले कांग्रेस की सेवा का मतलब देश सेवा समझा जाता था। लेकिन आज के औसत कांग्रेसी के बारे में यह धारणा बनती जा रही है कि–उसकी नजर देष सेवा के बजाय आत्मसेवा पर रहती है और जिस तरह से मंत्री, राजदूत या ऐसे ही अन्य पदों के लिए होड़ लगी है उससे बहुत से कांग्रेसी लोगों की नजर में गिर गए हैं'

तत्कालीन अमेरिकी राजदूत Chaster Bawels ने लिखा है कि ''1951–53 की अपेक्षा 1955 में जब दूसरी बार भारत आया, भ्रष्टाचार का बोलबाला अधिक था। भारतीय राज्यों के कई कैबिनेट मंत्री तक इसमें संलिप्त थे। कई जमींदार लोबियों की राज्य विधान सभाओं में अनियमित

गतिविधियों को भ्रष्टाचार से कम क्या कहा जाये, भारत में दलाली के रूप में भ्रष्टाचार का प्रथम मामला प्रतिरक्षामंत्री V. K. Krishan के दोषी सिद्ध होने पर प्रकाश में आया। मेनन उन दिनों ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे।

सार्वजनिक जीवन में पतन की शुरुआत विधिवत तरीके से 1956 के सिराजुद्दीन प्रकरण से होती है। 2. G. Specterm और S घोटाले के प्रेरणास्रोत प्रकरण लाइसेंस–परमिट राज की दुर्गंध और राजनेता और व्यापारी वर्ग के बीच सांठ–गांठ की शुरुआत यहीं से होती है। जाँच के दौरान पता चला कि राजनेताओ के साथ सिराजुद्दीन के संबंध कितने प्रगाढ़ थे। प्रजा सोषलिस्ट पार्टी के नेता सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने संसद में जांच की मांग की सिराजुद्दीन द्वारा कुछ बड़े नेताओं को नियमित रूप से दलाली देने का आरोप स्वीकार किया गया और अंत में 'खान और ईंधनमंत्री केशवदेव मालवीय ने कबूल किया कि उन्होंने दलाली ली है। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ सिराजुद्दीन ने अपने संपर्को का इस्तेमाल कर न केवल जांच रुकवायी बल्कि उसे चैकोस्लोवाकिया से O. N. G. C. के लिए तेल खनन उपकरणों के आयात का ठेका दिया। इस कार्य ने नेहरु सरकार की छवि पर प्रश्न चिह्न लगा दिया।

इसके बाद तो मानों घपले–घोटालों व भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गयी। नेतृत्वधारी वर्ग का नैतिक पतन भी पराकाष्ठा पर पहुँचने लगा। 1957 की मूंदड़ा काण्ड की हेरा–फेरी जिसमें वित्तमंत्री T. T. Krishnamachari, Finance Secretary H. M. Patel और L.I.C. के अध्यक्ष दोषी पाये गये। मूंदड़ा पर 160 करोड़ के घपले का आरोप था। पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के निर्माता समझे जाने वाले सरदार प्रताप सिंह कैरो के काले कारनामें, जिन्हें जवाहर लाल नेहरु का वरदहस्त प्राप्त था, की जांच के लिए न्यायाधीश सुधीर रंजन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बैठाया और इन्हें दोषी पाया गया। 24 मई 1971 का नागरवाला भारतीय स्टेट कांड में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मिली भगत की जांच के लिए P. Jagmohan Raddi की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया गया। नागरवाला की संदिग्ध मौत मामले की गंभीरता की ओर संकेत करती है। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के करतब, कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, अर्स की असलियत, आपातकाल के दुरुपयोग, मीडिया के दुरुपयोग इत्यादि भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधियों की गहरी संलिप्तता को दर्शाते हैं।

सन् 1968 की संजय गांधी की मर्यादाहीन मारुति, कुओं तेल काण्ड जिसमें उच्च पदों पर बैठे लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और समाज की पारंपरिक आचार संहिता को ध्वस्त किया था। 1982 का अब्दुल रहमान अंतुले और चुरहट कांड जिसमें अंतुले को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और चुरहट कांड में म. प्र. के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, चुरहट लाटरी कांड में उनके पुत्र अजय सिंह, उनके कई रिश्तेदार, रीवा के पूर्व महाराज आदि कथित रूप से जुड़े थे। मामला गरमाया न्यायमूर्ति रामलिंगम की अध्यक्षता में आयोग तो गठित किया गया लेकिन न्यायमूर्ति की संदिग्ध मृत्यु और मामले का लटकाना संशय की ओर ले जाता है।

सनसनीखेज बोफोर्स दलाली जोकि प्रतिभूति घोटाले तथा 2. G. Specterm और S.Bond की तुलना में काफी कम रकम बैठती है जोकि भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में माना गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी इनकी खरीद पर प्रश्नचिन्ह् लगाया था। रक्षा मामलों के राज्यमंत्री अरुण सिंह और अभिनेता अमिताभ बच्चन को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। स्वीडन के प्रधानमंत्री आलोफ पाल्मे की हत्या को भी इसी से जोड़कर देखा गया। विष्वनाथ प्रताप सिंह का इस मुद्दे को लेकर जननायक बनना और केंद्रीय सत्ता तक पहुँचना भी इसी कांड का परिणाम था। वी. पी. सिंह ने प्रधानमंत्री बनने पर 15 दिन के भीतर दलालों का पता लगाने का आश्वासन दिया था। लेकिन मामला आज तक लटका हुआ है और रहस्य खुलना अभी बाकी है।

इतिहास के बड़े घोटालों में से एक प्रतिभूति घोटाला जिसमें बैंकों के बड़े अफसर, सरकार के मंत्री और शेयर दलाल सरकारी नियम कायदों को लेकर जिस चालाकी से करोड़ों रुपये इधर–उधर करते रहे, उसे महाभ्रष्टाचार से कम क्या कहा जाये? प्रतिभूति घोटाला बताता है कि हमारी नौकरशाही भीतर से कितनी खोखली हो चुकी है। अभी यह पता नहीं लगा पाई कि कितनी रकम इस घोटाले में फंसी है। सरकार ने संयुक्त संसदीय जांच समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट जारी की है। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि वास्तविक दोषियों को छिपाया जा रहा है।

इसी तरह के कुछ बड़े–बड़े घोटाले आज देश की प्रतिष्ठा और सरकार की कार्यशैली पर वाट लगा चुके हैं। आज सरकार की ही लोक–लाज शर्मिंदा नहीं हुई बल्कि लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक का सर शर्म से झुक गया है। आदर्श–सोसाइटी घोटाला 2. G. Specterm और राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला फिर S. Bond के परत दर परत होते खुलासे और इन पर केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और ऊपर से सरकार का ध्यानाकर्षण कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को अलर्ट करना और जवाबी कार्यवाही में प्रधानमंत्री महोदय की सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सीमाओं में रहने की टिप्पणी ने सरकार के भ्रष्टाचार को खुले समर्थन को जगजाहिर कर दिया है। जिसकी जनता में सर्वत्र थू–थू हो रही है। आश्चर्य तो तब होता है जब इन सबके बावजूद एक दागी छवि वाले व्यक्ति को देश के पहरेदार मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर असंवैधानिक तरीके से नैतिक और कानूनी मर्यादाओं का हनन करते हुए आसीन कर दिया। जब पहरेदार ही चोर होंगे तो पहरा कौन दे भला? भ्रष्टाचार के प्रति उदारीकरण की नीति ने आम जन को कंगाल बनाकर रख दिया है। विपक्ष और भारी जनाक्रोश के बाद भी संयुक्त संसदीय जांच समिति के लिए सरकार का हामी न भरना बेषर्मी की सारी हदों को पार कर जाता है। एक लम्बी लेट लतीफी के बाद लोकपाल विधेयक की तैयारी और C.C.I.A. की तैयारी करना सरकार की विवेकहीनता से ज्यादा उसके भ्रष्ट आचरण को ही उजागर करता है।

प्रधानमंत्री देश के सार्वजनिक धन का न्यासी है और मंत्री परिषद उसी का विस्तार है। मुख्य सतर्कता आयुक्त पर अतिरिक्त सतर्कता की जिम्मेदारी होती है। सरकार को जवाब देह बनाने की संसदीय शक्ति सबसे बड़ी है इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार संस्थागत बन गया है और

इसने देश और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो चावल निर्यात घोटाला, सार्वजनिक प्रणाली, एल. आई. सी. हाउसिंग जैसे घोटालों के पंख लगाकर मंहगाई आसमान पर पहुँची है। सत्ताधीश छोड़ सब लुट रहे हैं। भ्रष्टाचार ही सत्यम है। देश भ्रष्टाचार से तबाह है।

संसदीय जनंतत्र में राजनीतिक तंत्र की खास भूमिका होती है। भ्रष्टाचार की राजनीतिक संस्कृति का विकास, इन सब अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि यह सब कांग्रेस सरकार ने ही किया है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे–विभिन्न रहस्योदघाटन कहीं वैसा ही माहौल न बना दे जैसा कि 'बोफोर्स सौदे में कथित दलाली के चलते राजीव गांधी के खिलाफ बन गया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद गवाँना पड़ा था। खैर भ्रष्टाचार की कथा अनंत है। जितना भी लिखा जाए कम है।

मैंने अपने शोध कार्य में भ्रष्टाचार को प्राथमिक स्तर पर विकास कार्यों में अर्थात् ग्रामीण विकास कार्यों के संदर्भ में वर्णित कर उसका गहन विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। चूँकि देश में भ्रष्टाचार विकास कार्यक्रमों के नाम पर प्रमुखतः देखा जाता है। अतः इसका अध्ययन ''विकास बनाम भ्रष्टाचार–ग्रामीण आँचलिक परिवेश में'' शीर्षक नाम से किया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से विकास की योजनायें चलाती रहती है परन्तु उनका लाभ सबसे गरीब तबकों को नहीं मिल रहा हैं मनरेगा के तहत एक लाख बारह हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं परंतु इसका कितना रुपया ठेकेदारों और बिचौलियों व अधिकारियों की जेब में गया कुछ ठिकाना नहीं। मैं अपने इस शोध में ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ ही विषयों को लेकर चल रहा हूँ; क्योंकि संसार में भ्रश्टाचार के इतने रूप हैं जितने कि मनुश्य के। भ्रष्टाचार से संबंधित एक विशिष्ट बात को भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सिर्फ न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो जाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ गवाह के सामने ही नहीं होता सिर्फ संबंधित पात्र ही उसके कर्ता–धर्ता होते है।

किसी निश्चित बैंक एकाउंट से लेन–देन, सुझाव पक्षपात दण्ड सिफारिश, षड़यंत्र, बेईमानी का लेखा–जोखा आदि किसी गवाह या अन्य की जानकारी में नहीं किया जाता है। इसमें बटवारे में अनुचितता, काम का न होना, ईर्ष्या स्वयं का लाभार्थी न होना, दूसरे को तंग करना या फिर कभी–कभी देश प्रेम जाग जाने के कारण इसका भण्डा फूट जाता है। लेकिन न्यायालय में प्रमाण नहीं मिलने के कारण न्यायालय से भी वह प्रमाणित नहीं हो पाता है। जबकि वो सच होता है क्योंकि बिना आग के धुँआ नहीं उठ सकता। इसीलिए प्रमाणित नहीं होना ही भ्रष्टाचार नहीं है। इसके हजारों हाथ हैं यह अदृश्य रूप से अपना काम करता है तथा भ्रष्ट काम करने वाले न्यायालय की सीमा को जानते हैं और उसकी परिधि के बाहर काम करते हैं। इसी कारण भ्रष्टाचार का ग्रामीण स्तर पर जहाँ आम जन को इसकी समझ तक नहीं होती, इसको सार्वजनिक करने के लिए व इसकी पुष्टि करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से अधिक परिवेश के अनुभवी जनों की प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं और अनुभवों को भी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति एक लाइब्रेरी के तुल्य अनुभव रखता है। चीन में व्यक्ति की मृत्यु पर कहा जाता है कि–''एक देह

नहीं वरन् एक लाइब्रेरी जलकर खत्म हो गयी है'' अतः इन महानुभावों का प्रयोग पूर्णतः तार्किक होगा। जोकि सच के प्रकटीकरण का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।

'Transperensie international' में खुलासा किया गया है कि वर्ष 2009 में भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान 84 वां तथा वर्ष 2010 में 178 देशों की सूची में भारत का स्थान 87 वां रहा। अर्थात् भारत में भ्रष्टाचार का सूचकांक 3 स्थान और ऊपर हो गया है।

'Transperensie India की Director Anupma Jha ने बताया है कि 2.G. Spectrum, S. Band. Rashtramantal Game और U.P. का खाद्यान्न घोटाले, जाँच तथा आये दिन हो रहे खुलासे से 2011 में भारत की भ्रष्टाचार रैंक काफी गिर सकती है।

भारत गाँवों का देश है। करीब 7 लाख गाँव हैं जो अपने में पूर्ण हैं और यही भारत के अस्तित्व को बचाए हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था पर ही आधारित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने ''जय जवान जय किसान'' का नारी यूँ ही नहीं दिया था। शास्त्री जी ने एक बार संसद में कहा भी था कि–''देश की समृद्धि के लिए देश के किसान का खुशहाल होना प्रथम शर्त है। माननीय राजेश पायलट जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि–''देश की समृद्धि और विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों के मध्य से होकर गुजरता है।

लेकिन दुर्भाग्य से गाँव की उन्नति के लिए आज तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, ना ही उस पर चिंता की गई, ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार तो कहीं दूर की बात है। सिर्फ सुविधा के नाम पर मकान बिजली, नाला रोड़, पानी पर लाखों करोड़ो खर्च किया जा रहा है और परिणाम लगभग षून्य है। पूरे भारत वर्ष में करीब 7 लाख गाँव और और डेढ लाख पंचायत हैं यानि प्रति पंचायत औसतन करीब पाँच ही गाँव आते हैं। किसी–किसी में एक गाँव तो कहीं 6–7 गाँव की पंचायत हैं जो दूर–दूर अवस्थित हैं। हम प्रत्येक वर्ष एम. एल. ए. पर 20,000 करोड़ रुपये तथा एम. पी. फण्ड से 10,000 करोड़ एन. जी. ओ. पर 20,000 करोड़ खर्च करते हैं जबकि सिर्फ 60,000 करोड़ सालाना से गाँवों का नक्शा बदला जा सकता है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो षायद ग्रामीण विकास की इतनी बदहवासी और दुर्गति नहीं होती। यदि गाँव का विकास समुचित प्रकार से होता तथा ग्रामीण विकास और सरकार इससे जुड़े भ्रष्टाचार को गम्भीरता से ले लेती तो शायद पूरे देश को रोटी खिलाने वाला किसान वर्ग आज आत्म हत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता। ''सम्पूर्ण देश के समाज सेवी, राष्ट्रभक्त और जन प्रेमी संसद सरीखे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार निवारण के लिए लोकपाल विधेयक की माँग को लेकर तो अनशन पर बैठे हैं,[2] लेकिन आज तक किसी ने ग्रामीण भ्रष्टाचार का मुद्दा शायद ही उठाया हो? संसद भवन के आगे, जंतर–मंतर पर तो विरोध करने पहुँच गए पर शायद ही किसी ने गाँव तहसील या कचहरी पर किसी प्रशासनिक नौकरशाह अथवा जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला उठाया हो और अनषन पर बैठे हों। भ्रष्टाचार का कोपभाजन सबसे अधिक ग्रामीण भोली–भाली जनता को ही बनना पड़ता है। मैं पूछता हूँ उन ईमानदार समाजसेवियों से कि–उनके आपने गाँव, कस्बे या शहर में जिला तो दूर की बात है किसी ने रिश्वत दी या ली नहीं होगी? क्या उनके अपने आँचलिक परिवेश में कभी उन्हें कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिला? शायद ही इसका उत्तर नहीं में मिलेगा।

देश के औद्योगिक घराने और पूँजीपति वर्ग अपना उत्पादन बढाने एवं लाभ के लिए समस्त संवैधानिक विधि नैतिक कायदे कानूनों को अपने पैरों तले रौंदते ही नहीं अपितु अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें तोड़ते–मरोड़ते हैं। 2 G Spectrum भी इसी का एक रूप कहा जा सकता है। अकेले ए. राजा को दण्ड देकर सरकार ने एक पूरी भ्रष्ट लाबी को बचाकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली है। जोकि अपर्याप्त ही नहीं वरन् अतार्किक भी हैं। जब देश के उद्योगपति वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए कानून में छेड़छाड़ की जाती है तब षायद कोई बिरला ही ईमानदार इसके विरुद्ध आवाज उठाता हो। जनता के धन से अमीरों की जेबें भरी जा रही हैं। अमीर और अमीर एवं गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक लोकपाल विधेयक ही पर्याप्त नहीं। इसे समाप्त करने के लिए इसकी सही तरीके से नब्ज टटोलना जरूरी हो गया है। इसके नाश के लिए भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष की शाखाओं पर नहीं वरन् इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाना अत्यावश्यक हैं। इसके लिए इसके प्रादुर्भाव के कारण और प्रादुर्भाव के स्थान को चिन्हित करना जरूरी हो गया है। ग्रामीण संस्कृति वाले देश में ग्रामीण भ्रष्टाचार से निगाहें हटाकर संसद और जंतर–मंतर पर अनशन पर बैठकर भ्रष्टाचार–उन्मूलन–क्रांति की सफलता की परिकल्पना भले ही बुद्धिजीवी समाजसेवी वर्ग ने बना ली हो, देश का कृषक और मजदूर, खासकर ग्रामीण तबका बना पायेगा, संदेह से परे नहीं। अन्ना हजारे साहब का भ्रष्टाचार कि विरुद्ध गाँधावादी मार्ग अपनाते हुए अनषन पर बैठना वाकई तारीफे काबिल हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी दष्ढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचायक है। हजारे साहब को देश के कोने–कोने से समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन शायद ही कोई किसान नेता वहाँ पहुँचा हो, क्योंकि वह जानते हैं कि किसान वर्ग के शोषण के विरुद्ध शायद ही कोई चिंतित हो। यह सोचकर ऐसे किसी आंदोलन से पैर खींचकर किसान घर की चार दीवारी में उदासीन होकर बैठ जाता है। इसीलिए यह कहना अतार्किक होगा कि हजारे साहब को प्रत्येक वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है।

संदर्भसूची

[1] *"Ministers Misconducts" Written By 'A. G. Noorahie'*

[2] *सी. एम. झा : ''भ्रष्टाचार समस्या और समाधान''–ग्राम विकास के संदर्भ में पृष्ठ–111–112*